भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 - 197
उत्तर देने की तारीख - 6 दिसम्बर, 2013

मोबाइल टॉवरों में हरित ऊर्जा का उपयोग

197. श्रीमती वसन्ती स्टान्ली :

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोबाइल टॉवरों में नवीकरणीय हरित ऊर्जा के उपयोग के संबंध में भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है;
(ख) क्या निजी क्षेत्र उनकी सिफारिशों को लागू करने में सफल रहे हैं एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इन सिफारिशों को लागू करने में दूरसंचार कंपनियों के समक्ष क्या प्रमुख कठिनाइयां पेश आ रही हैं?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण (ट्राई) ने "हरित दूरसंचार के प्रति दृष्टिकोण" पर दिनांक 12.04.2011 को दी गई अपनी सिफारिशों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके और दूरसंचार क्षेत्र में कार्बन-उत्सर्जन में कमी लाकर जीवाश्म-इन्धन को बचाने पर बल दिया है। ट्राई की सिफारिशों के आधार पर, दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार क्षेत्र के हरितकरण तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी(आरईटी) साधनों और ऊर्जा सक्षम उपस्करों का उपयोग करके कार्बन-उत्सर्जन में अपेक्षित कमी को हासिल करने के लिए दिनांक 23.01.2012 को निम्नलिखित व्यापक निर्देश जारी किए हैं।

(i) वर्ष 2015 तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी टॉवरों के कम से कम 50 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों के 20 प्रतिशत टॉवरों को हाइब्रिड पावर (नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी(आरईटी) + ग्रिड पावर) द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाएगी; इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्र के 75 प्रतिशत टॉवर और शहरी क्षेत्र के 33 प्रतिशत टॉवरों को वर्ष 2020 तक हाइब्रिड पावर से ऊर्जा प्रदान की जाएगी। दूरसंचार मोबाइल नेटवर्क के लिए भी कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

जारी...2

(ii) वर्ष 2020 तक प्रत्येक बेस ट्रांसीवर स्टेशन(बीटीएस) की कुल ऊर्जा खपत 500 वॉट से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(iii) सेवा प्रदाताओं को वर्ष 2020 तक ग्रामीण क्षेत्रों में आधार वर्ष के कार्बन फुटप्रिंट स्तरों के अधिकतम 50 प्रतिशत का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से और शहरी क्षेत्रों में आधार वर्ष के कार्बन फुटप्रिंट स्तरों के, अधिकतम 66 प्रतिशत के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्बन क्रेडिट मानकों के अनुरूप एक "कार्बन क्रेडिट नीति" तैयार करनी चाहिए ।

(iv) सेवा प्रदाताओं को मोबाइल नेटवर्क के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए वर्ष 2012-2013 तक 5 प्रतिशत, वर्ष 2014-2015 तक 8 प्रतिशत, वर्ष 2016-2017 तक 12 प्रतिशत और वर्ष 2018-2019 तक 17 प्रतिशत तक के लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।

(ख) कुछ प्रगति की गई है । दूरसंचार विभाग ने यूएसओएफ और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (एमएनआरई) मंत्रालय की सहायता से तकनीकी साध्यता, तथा व्यवहार्यता सम्बंधी मुद्दों की जांच करने के लिए हरित ऊर्जा (एसपीवी एवं एसपीवी विंड हाईब्रिड) का उपयोग करके वर्ष 2010-11 में यूएसओएफ चरण-I स्थलों में 20 पायलट परियोजनाएं चलाईं। इन पायलट परियोजनाओं के परिणामों के आधार पर दूरसंचार प्रचालकों द्वारा एमएनआरई की सहायता से 400 आरईटी परियोजनाएं क्रियान्वित की गई । इसके अतिरिक्त, दूरसंचार उद्योग ने आरईएससीओ (नवीनीकरण ऊर्जा सेवा कम्पनी) मॉडल पर, 2217 आरईटी परियोजनाएं चलाई हैं। बहुत से प्रचालक इन प्रयासों को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं।

(ग) दूरसंचार कंपनियों द्वारा इन सिफारिशों के कार्यान्वयन में झेली जा रही प्रमुख कठिनाइयां निम्नलिखित हैं :

(i) नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी (आरईटी) ऊर्जा मुहैया कराने के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) अधिक है। उद्योग वित्तीय सहायता/व्ययहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए सरकार से सहायता चाहता है। एमएनआरई ने संकेत दिए हैं कि वह धन की कमी के कारण दूरसंचार टॉवरों को राज सहायता देने की स्थिति में नहीं है।

(ii) दूरसंचार केंद्र दूर-दूर स्थित हैं तथा आरईटी केंद्रों का प्रचालन एवं अनुरक्षण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

*****